

भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 746
07 फरवरी, 2023 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक वाहन नीति

746. कुमारी राम्या हरिदास:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार उन राज्यों की योजनाओं/नीतियों से अवगत है जिनके पास समर्पित इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या उक्त राज्यों की नीतियों और फेम योजना के साथ अभिसरण के कोई अवसर है; और
- (घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को शीघ्र अपनाने के लिए अभिसरण की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) से (घ): जी हां, चौबीस राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, असम, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल) ने विशिष्ट इलेक्ट्रिक वाहन नीतियों को अनुमोदित/अधिसूचित किया है। इसके अलावा, चार राज्यों नामतः पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीतियों का मसौदा जारी किया है। राज्य की नीतियां इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के अनुरूप हैं।
